No: PLT/PAN/News-85
Dt: 06/08/2016

दामोदर घाटी निगम
जन–सम्पर्क विभाग : पंचेत
शीर्षक, स्थान एवं प्रसिद्धि दिनांक

01. हिन्दुस्तान
02. प्रभात खबर

धनबाद

प्रभात खबर | धनबाद, शनिवार | 6.08.2016 | 07

# एक साल में शहरी क्षेत्र की बिजली होगी दुरुस्त : एमडी

- 157 करोड़ रुपये होंगे खर्च, जर्जर तार, ट्रांसफॉर्मर बदले जायेंगे

वरीय संवाददाता › धनबाद

ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक राहुल पुरवार ने कहा कि अगले एक साल के अंदर शहरी क्षेत्र की बिजली आपूर्ति में सुधार हो जायेगी. इन्फ्रास्ट्रक्चर पर धनबाद में 157 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

श्री पुरवार डीवीसी की ओर से आयोजित कंज्यूमर मीट के बाद सरायढेला स्थित एक होटल में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग को सुदृढ़ करने के लिए इसे तीन पार्ट में बांटकर काम किया जा रहा है.

पहले पार्ट में शहरी क्षेत्रों में जहां जो पुराने उपकरण, जर्जर तार, कम लोड वाले ट्रांसफॉर्मर बदले जायेंगे. एआरपीडीआरपी-टू के तहत 157 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यह योजना एक साल में पूरी हो जायेगी. इसके अलावा आइपीडीएस योजना के तहत भी बहुत काम होंगे. इस योजना के तहत 80 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

बातचीत करते राहुल पुरवार व उपस्थित अन्य. फोटो | प्रभात खबर

**15 सौ टोले का होगा विद्युतीकरण :** ग्रामीण क्षेत्रों में दीन दयाल योजना के तहत अगले साल तक सभी टोला का विद्युतीकरण कर लिया जायेगा. धनबाद में सभी गांवों का विद्युतीकरण हो गया है, सिर्फ 15 सौ टोले बच गये हैं.

**ट्रांसमिशन व्यवस्था होगी दुरुस्त, बनेंगे नये ग्रिड:** एमडी ने स्वीकार किया उनके यहां ट्रांसमिशन व्यवस्था अभी दुरुस्त नहीं है. अभी डीवीसी के ग्रिड से ही बिजली आपूर्ति की जा रही है, इसलिए भी थोड़ी दिक्कत होती है. पूरे डीवीसी कमांड एरिया में 850 मेगावाट बिजली हमलोग ले रहे हैं. ग्रिड बन जाने के बाद जहां-जहां से पावर आने हैं, वहां का सिस्टम दुरुस्त हो जायेगा.

**महंगी बिजली खरीदते और सस्ती में बेचते हैं :** एमडी ने कहा कि उनके यहां जो भी कंज्यूमर हैं, वे घरेलू उपभोक्ता हैं. हमलोग डीवीसी से 4.80 रुपये प्रति यूनिट डीवीसी से बिजली खरीदते हैं और 2.20 रुपये प्रति यूनिट कंज्यूमर को देते हैं.

**अगले चार माह में धनबाद नेशनल ग्रिड से जुड़ जायेगा :** एमडी ने बताया कि गोविंदपुर के कांड्रा में ग्रिड का काम पूरा हो चुका है. इसे जोड़ने का काम चल रहा है. 60- 70 टावर बनाने बाकी रह गये हैं. दुमका व अन्य स्थानों से लाइन जोड़ी जायेगी.

## डीवीसी पावर सप्लाइ में और सुधार करेगा : लेगेंस्टे

डीवीसी के चेयरमैन ए लेगेंस्टे ने यहां कहा कि डीवीसी की पावर क्वालिटी में जो भी कमी है, उसमें जल्द ही सुधार किया जायेगा. उन्होंने अपने सभी उपभोक्ताओं को टिकाऊ और सस्ती बिजली देने का आश्वासन दिया. श्री लेगेंस्टे शुक्रवार को स्थानीय एक होटल में कंज्यूमर मीट में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि अभी पावर में थोड़ी – बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन इसमें सुधार के लिए प्रयास किये जा रहे हैं. सारी कमियां शीघ्र दूर हो जायेगी. चेयरमैन अपने उपभोक्ताओं द्वारा रखे जा रहे सुझाव के जवाब में उक्त बातें कहीं. उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में काम हो रहा है. बैठक में डीवीसी के अमिताभ नायक, ए देवनाथन, हजारीबाग, जमशेदपुर एवं अन्य जगहों डीवीसी के पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग के एमडी राहुल पुरवार, धनबाद के जीएम पीआर रंजन, अधीक्षण अभियंता विनय कुमार, कार्यपालक अभियंता रवि प्रकाश कंज्यूमर में रेलवे, बीसीसीएल, सीसीएल, सेल, आइएसएम सहित कुल 38 विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे.

कनेक्शन जोड़ने में चार माह का समय लगेगा. उसके बाद धनबाद नेशनल ग्रिड से जुड़ जायेगा.

**लगेंगे सभी घरों में मीटर :** श्री पुरवार ने बताया कि अभी सौ घरों में 40 घरों में ही मीटर लगे हैं. अगले साल तक सभी घरों में मीटर लगा दिये जायेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों के भी सभी घरों में मीटर लगाये जायेंगे. मौके पर जीएम पीआर रंजन, अधीक्षण अभियंता विनय कुमार, कार्यपालक अभियंता रवि प्रकाश उपस्थित थे.

# डीवीसी व पेयजल विभाग के बीच पानी को ले विवाद

- शहरी जलापूर्ति योजना का काम रुका
- विभाग ने चिनपं को भुगतान के लिए लिखा पत्र

**चिरकुंडा.** पेयजल व स्वच्छता विभाग तथा डीवीसी के बीच आपसी विवाद का खमियाजा चिरकुंडा नगर पंचायत भुगत रहा है. नपं क्षेत्र की 26 करोड़ की महत्वाकांक्षी शहरी जलापूर्ति योजना का काम इसके कारण रुक गया है. पेयजल व स्वच्छता विभाग धनबाद के कार्यपालक अभियंता ने नपं चिरकुंडा को रॉ वाटर के एवज में वर्ष 1980 से 30 अप्रैल 16 तक के लिए दो करोड़ 35 लाख 42 हजार 737 रुपया बकाया भुगतान का पत्र दिया है. वहीं डीवीसी एमआरओ विभाग ने नपं को 0.1 एमजीडी रॉ वाटर लेने के लिए करार करने तथा पुरानी समस्या को निपटाने के लिए पत्र भेजा है. डीवीसी ने विभाग को लगभग साढ़े 11 करोड़ रुपया बकाया भुगतान के लिए भी पत्र भेजा है. माना जा रहा है कि विभाग द्वारा रॉ वॉटर का बकाया भुगतान नहीं करने के कारण ही डीवीसी राइजिंग पाइप बिछाने की अनुमति नहीं दे रही है. डीवीसी एमआरओ एसके माजी ने पत्र में कहा है कि नपं चिरकुंडा को भेजे पत्र 11 अक्तूबर 1968 से 10 अक्तूबर 2008 तक के लिए ही रॉ वाटर लेने का समझौता हुआ था.

समाचार की छायाप्रति अवलोकनार्थ प्रेषित :–

01. उप मु0 अभि0 सह परियोजना प्रधान, दाघानि, पंचेत।
02. उप मुख्य अभियन्ता(असै0), दाघानि, पंचेत।
03. मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी, दाघानि, कोलकाता।
04. अपर निदेशक–मानव संसाधन, दाघानि, पंचेत।

नवीन कुमार
06/08/2016

नवीन कुमार
विशेष सहायक जनसम्पर्क
दाघानि, पंचेत
PGDBA (HR) 2 Yrs FT,
PGD (Public Relations).

Scanned by CamScanner